

शाक-स्य की पूर्व-अपराधी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के विषय अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल—505/डब्ल्यू.पी.



पंजी क्रमांक भोपाल दिवसीय
132 (एन. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 1980—ज्येष्ठ 16, शके 1902

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक:

(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन;

(3) संसद् से पुरःस्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश;

(2) मध्यप्रदेश अधिनियम;

(3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम;

(2) अन्तिम नियम;

भाग ४ (ख)

संसद् के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1975

क्र. 37635-इक्कीस-अ(वि.स.)-75.—भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से “भारत के राजपत्र”, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 क, दिनांक 2 जून 1975 में प्रकाशित किये गये दि पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 (क्रमांक 39 सन् 1972) के हिन्दी अनुवाद को, जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (क्रमांक 19 सन् 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सं. जु. सुराणा, सचिव.

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम सं० 39)

(1 जुलाई, 1975 को यथाविद्यमान)

[21 अगस्त, 1972]

कारखानों, छानों, तेलक्षेत्रों, वागानों, पत्तनों, रेल कम्पनियों, दुकानों अथवा
अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए
एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक
विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपदान संदाय अधिनियम,
1972 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार, नाम
होना तथा
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :
परन्तु जहां तक इसका सम्बन्ध बागानों या पत्तनों से है, इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा।

(3) यह अधिनियम—

- (क) प्रत्येक कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी को;
- (ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा स्थापन को, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा नियोजित थे ;
- (ग) ऐसे अन्य स्थापनों अथवा स्थापनों के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों अथवा नियोजित थे ;

लागू होगा।

(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “समुचित सरकार” से अभिप्रेत है—

(i) निम्नलिखित स्थापनों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, अर्थात् :—

- (क) केन्द्रीय सरकार के, अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्थापन,
- (ख) ऐसे स्थापन जिनकी एक से अधिक राज्य में शाखाएं हों,
- (ग) केन्द्रीय सरकार के, अथवा उसके नियंत्रणाधीन कारखाने के स्थापन,
- (घ) किसी महापत्तन, खान, तेलक्षेत्र अथवा रेल कम्पनी के स्थापन,

और

(ii) किसी अन्य दशा में, राज्य सरकार ;

(ख) “सेवा का सम्पूरित वर्ष” से एक वर्ष की निरन्तर सेवा अभिप्रेत है ;

(ग) “निरन्तर सेवा” से अभिप्रेत है अविच्छिन्न सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, कामबन्दी, हड़ताल अथवा तालाबन्दी अथवा कार्यावरोध, जो सम्बन्धित कर्मचारी की किसी वृत्ति के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या पश्चात्।

स्पष्टीकरण 1—किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो एक वर्ष से अविच्छिन्न सेवा में नहीं है, तब यह समझा जाएगा

कि वह निरन्तर सेवा में है जब वह उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी नियोजक द्वारा,—

- (i) यदि किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित हो तो कम से कम 190 दिनों के लिए, अथवा
- (ii) किसी अन्य दशा में, तब के सिवाय जब कि वह किसी मौसमी स्थापन में नियोजित हो, कम से कम 240 दिन के लिए,

वास्तव में नियोजित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2—किसी मौसमी स्थापन के कर्मचारी के बारे में तब यह समझा जाएगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब उसने उन दिनों के, जिनमें वह स्थापन उस वर्ष के दौरान चालू रहा, कम से कम पचहत्तर प्रतिशत दिन वास्तव में काम किया है ;

- (घ) “नियंत्रक प्राधिकारी” से समुचित सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ङ) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है (शिक्षु से भिन्न) ऐसा कोई व्यक्ति जो एक हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर किसी स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान में कुशल, अर्ध-कुशल, अथवा अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षण सम्बन्धी, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे ऐसे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हैं अथवा विवक्षित, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता जो प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है, अथवा जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, अथवा जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950, अथवा नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन है।

1950 का 45

1950 का 46

1957 का 62

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पांच वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए एक हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर नियोजित किया गया हो और तत्पश्चात् किसी समय एक हजार रुपए प्रतिमास से अधिक की मजदूरी पर नियोजित किया जाए, उस कालावधि की बावत उपदान, जिसके दौरान ऐसा कर्मचारी एक हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर नियोजित रहा हो, उसके द्वारा उस कालावधि के दौरान प्राप्त की गई मजदूरी के आधार पर अवधारित किया जाएगा ;

- (च) “नियोजक” से, किसी ऐसे स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के सम्बन्ध में —
 - (i) जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की है, अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, समुचित सरकार द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत है, अथवा जहां कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं

किया गया है वहाँ सम्बन्ध संवाक्य अथवा विभाग का प्रधान अभिप्रेत है,

(ii) जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की है अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है अथवा जहाँ कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहाँ स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है,

(iii) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसका स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के कार्यकलाप पर अंतिम नियंत्रण है, तथा जहाँ उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए हैं, चाहे वह प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहाँ वह व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड) "कारखाना" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ड) में है; 1948 का 63

(ज) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "कुटुम्ब" में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगे, अर्थात्:—

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में, वह स्वयं, उसकी पत्नी, उसकी विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र, यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान,

(ii) महिला कर्मचारी की दशा में, वह स्वयं, उसका पति, उस की विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व-मृत पुत्र, यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान :

परन्तु यदि कोई महिला कर्मचारी, नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित सूचना द्वारा, अपने पति को अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने की वांछा अभिव्यक्त करती है तो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, पति और उसके आश्रित माता-पिता ऐसी महिला कर्मचारी के कुटुम्ब में सम्मिलित नहीं समझे जाएंगे जब तक कि उक्त सूचना उक्त महिला कर्मचारी द्वारा तत्पश्चात् वापस न ले ली जाए।

स्पष्टीकरण—जहाँ कर्मचारी की स्वीय विधि के अधीन उसके द्वारा संतान का दत्तक ग्रहण अनुज्ञात है वहाँ उसके द्वारा विधिपूर्वक दत्तक ग्रहीत संतान उसके कुटुम्ब में सम्मिलित समझी जाएगी, और जहाँ किसी कर्मचारी की संतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर ली गई है और ऐसा दत्तक ग्रहण, ऐसा दत्तक ग्रहण करने

वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन, वैध है वहां ऐसी संतान कर्मचारी के कुटुम्ब से अपवर्जित समझी जाएगी;

- 1908 का 15 (झ) "महापत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खण्ड (8) में है;
- 1952 का 35 (ञ) "खान" का वही अर्थ है जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (जा) में है;
- (ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- 1948 का 53 (ठ) "तेलक्षेत्र" का वही अर्थ है जो तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के खण्ड (ड) में है;
- 1951 का 69 (ड) "बागान" का वही अर्थ है जो बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खण्ड (च) में है;
- 1908 का 15 (ढ) "पत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खण्ड (4) में है;
- (ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- 1890 का 9 (त) "रेल कम्पनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3 के खण्ड (5) में है;
- (थ) "निवृत्ति" से कर्मचारी की सेवा का, अधिवर्षिता पर से भिन्न रूप में, पर्यवसान अभिप्रेत है;
- (द) किसी कर्मचारी के संबंध में "अधिवर्षिता" से अभिप्रेत है—
- (i) कर्मचारी द्वारा उस आयु की प्राप्ति जो सेवा की संविदा अथवा शर्तों में ऐसी आयु के रूप में नियत की गई है जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी नियोजन रिक्त कर देगा; तथा
 - (ii) किसी अन्य दशा में, कर्मचारी द्वारा अठ्ठावन वर्ष की आयु की प्राप्ति ;
- (ध) "मजदूरी" से वे सब उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कर्तव्यारूढ़ होने अथवा छुट्टी पर होने की दशा में अर्जित की जाती हैं तथा जो उसे नकद संदत्त की जाती हैं अथवा संदेय हैं तथा इसके अन्तर्गत महंगाई भत्ता है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई बोनस, कमीशन, गृह-किराया भत्ता, अतिकाल मजदूरी और कोई अन्य भत्ता नहीं है।

3. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे।

4. (1) कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात् उपदान का संदाय। कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसको—

- (क) उसकी अधिवर्षिता पर, अथवा
- (ख) उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर, अथवा
- (ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निःशक्तता पर,

उपदान संदेय होगा :

परन्तु पांच वर्ष की निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होगा जहां किसी कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या निःशक्तता है :

परन्तु यह और कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसे संदेय उपदान उसके नामनिर्देशिती को अथवा, यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो, उसके वारिसों को दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निःशक्तता से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए असमर्थ बना देती है जिसे वह उस दुर्घटना या रोग के पूर्व, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई है, करने के लिए समर्थ था ।

(2) नियोजक कर्मचारी को, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अथवा छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा सबसे अन्त में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित पन्द्रह दिनों की मजदूरी की दर से उपदान देगा :

परन्तु मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यवसान के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की कालावधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालिक कार्य के लिए संदत्त मजदूरी गणना में नहीं ली जाएगी :

परन्तु यह और कि मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी की दशा में, नियोजक प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन की मजदूरी की दर से उपदान का संदाय करेगा ।

(3) कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम बीस मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगी ।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिए जो अपनी निःशक्तता के पश्चात्, घटी हुई मजदूरी पर, नियोजित किया गया है, उसकी निःशक्तता के पूर्व की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी उसके द्वारा उस कालावधि के दौरान प्राप्त की गई मजदूरी मानी जाएगी और उसकी निःशक्तता के पश्चात् की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी इस प्रकार घटी हुई मजदूरी मानी जाएगी ।

(5) इस धारा की कोई बात किसी पंचाट अथवा नियोजक के साथ करार या संविदा के अधीन उपदान के और अच्छे निबन्धन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जिस कर्मचारी की सेवाएं उसके किसी ऐसे कार्य या जानबूझकर

किए गए ऐसे लोग अथवा उपेक्षा के कारण, जिनमें कि नियोजक की सम्पत्ति की हानि, नुकसान अथवा विनाश हुआ है, समाप्त कर दी गई है, उसका उपदान इस प्रकार हुए नुकसान या हानि की मात्रा तक समपहृत कर लिया जाएगा;

(ख) कर्मचारी को संदेय उपदान पूर्णतः समपहृत कर लिया जाएगा—

- (i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके बलवात्मक अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसकी ओर से किए गए किसी अन्य हिंसात्मक कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं, अथवा
- (ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं जो नैतिक अधमता वाला अपराध है, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसा अपराध अपने नियोजन के दौरान किया जाता है।

5. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान को, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, यदि समुचित सरकार की राय में ऐसे स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के कर्मचारियों को उपदान या पेंशन संबंधी ऐसे फायदे प्राप्त हो रहे हैं जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त फायदों से कम अनुकूल नहीं हैं।

छूट देने की शक्ति।

6. (1) प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनार्थ नामनिर्देशन करेगा।

नामनिर्देशन।

(2) कर्मचारी अपने नामनिर्देशन में, इस अधिनियम के अधीन उसे संदेय उपदान की रकम, एक से अधिक नामनिर्देशिनी के बीच वितरित कर सकेगा।

(3) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा, तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, जो उसके कुटुम्ब का सदस्य नहीं है, शून्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किन्तु यदि तत्पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन तत्काल अविधिमान्य हो जाएगा और कर्मचारी, उतने समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अपने कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करेगा।

(5) उपधारा (3) तथा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशन का उपांतरण, कर्मचारी द्वारा किसी भी समय, नियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, देने के पश्चात् किया जा सकेगा।

(6) यदि नामनिर्देशिनी की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है तो नामनिर्देशिनी का हित कर्मचारी को प्रतिवर्तित हो जाएगा और कर्मचारी ऐसे हित के सम्बन्ध में, विहित प्ररूप में, नया नामनिर्देशन करेगा।

(7) यथास्थिति, प्रत्येक नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नाम-निर्देशन में परिवर्तन, कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को भेजा जाएगा जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

उपदान की रकम का अवधारण।

7. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय प्राप्त करने का पात्र है अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, नियोजक को, ऐसे उपदान के संदाय के लिए उतने समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, लिखित आवेदन भेजेगा।

(2) जैसे ही उपदान संदेय हो जाता है नियोजक, चाहे उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन किया गया है अथवा नहीं, उपदान की रकम अवधारित करेगा और उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है, तथा नियंत्रक प्राधिकारी को भी इस प्रकार अवधारित उपदान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित सूचना देगा।

(3) नियोजक, उपदान की रकम का उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है, उतने समय के भीतर जो विहित किया जाए, संदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(4) (क) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम के बारे में अथवा उपदान के संदाय के लिए किसी कर्मचारी के दावे की अनुज्ञेयता के बारे में अथवा उसके सम्बन्ध में, अथवा उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद है तो नियोजक, उतनी रकम जितनी कि वह उपदान के रूप में अपनी ओर से संदेय स्वीकार करता है, नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर देगा।

स्पष्टीकरण—जहां इस खण्ड में विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत कोई विवाद है वहां कर्मचारी नियंत्रक प्राधिकारी से ऐसी कार्रवाई करने के लिए आवेदन कर सकेगा जैसी कि खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी, सम्यक् जांच के पश्चात् तथा विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम का अवधारण करेगा, तथा, यदि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप, नियोजक द्वारा जमा की गई रकम से अधिक रकम संदेय पाई जाती है तो नियंत्रक प्राधिकारी, नियोजक को उतनी रकम जितनी कि उसके द्वारा जमा रकम के आधिक्य में पाई गई है, संदाय करने का निदेश देगा।

(ग) नियंत्रक प्राधिकारी जमा की गई रकम, जिसके अन्तर्गत नियोजक द्वारा जमा की गई अधिक रकम, यदि कोई हो, भी है, उसके हकदार व्यक्ति को देगा।

(घ) खण्ड (क) के अधीन रकम जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र, नियंत्रक प्राधिकारी उस जमा रकम का संदाय—

(i) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी है तो उसी को, अथवा

(ii) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी नहीं है तो, यदि नियंत्रक प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदक के उपदान की रकम प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है, कर्मचारी के नामनिर्देशिनी या वारिस को,

करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन जांच करने के प्रयोजनार्थ, नियंत्रक प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय होती

1908 का 5

हैं, अर्थात् :—

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

1860 का 45

(6) इस धारा के अधीन कोई जांच भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में, तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ, न्यायिक कार्यवाही होगी।

(7) उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, समुचित सरकार को, अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि, यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था, तो उक्त सरकार या प्राधिकारी उक्त अवधि को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(8) यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा अथवा उलट सकेगा।

8. यदि इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान की रकम नियोजक द्वारा, विहित समय के भीतर, उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त नहीं की जाती है तो नियंत्रक प्राधिकारी, व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, कलक्टर को उस रकम के लिए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो, विहित समय के अवसान की तारीख से उस पर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि व्याज सहित उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करेगा तथा उसे उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त करेगा।

उपदान की वसूली।

9. (1) जो कोई, किसी ऐसे संदाय से बचने के प्रयोजनार्थ जो उसे इस अधिनियम के अधीन करना है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा संदाय करने से बचने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ, जानबूझकर कोई मिथ्या कथन अथवा मिथ्या व्यपदेशन करेगा अथवा कराएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास-तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

शास्तियां।

(2) वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करेगा, अथवा उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु जहां अपराध इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान के असंदाय से संबंधित है वहां नियोजक कारावास से, जिसकी अवधि, तीन मास से कम की न

होगी, दण्डनीय होगा, सिवाय तब के जब अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, इस राय का हो कि कम अवधि के कारावास से या जुर्माने के अधिरोपण से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी।

नियोजक को
कतिपय मामलों
में दायित्व से
छूट।

10. जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित है वहां वह, उसके द्वारा सम्यक् रूप से किए गए परिव्राद पर और परिव्रादी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन पूर्ण दिनों की लिखित सूचना देने पर, इस बात का हकदार होगा कि किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है, उस आरोप की सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर, न्यायालय के समक्ष लाया जाए; और यदि अपराध का किया जाना साबित हो जायें के पश्चात्, नियोजक न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है—

(क) कि उसने इस अधिनियम का निष्पादन कराने के लिए सम्यक् तत्परता बरती है, तथा

(ख) कि उक्त अन्य व्यक्ति ने उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता के बिना अपराध किया है,

तो वह अन्य व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा और उसी प्रकार के दण्ड का भागी होगा मानो वह नियोजक हो, और नियोजक ऐसे अपराध की बाबत इस अधिनियम के अधीन हर दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा :

परन्तु यथापूर्वोक्त बात को साबित करने में नियोजक की शपथ पर परीक्षा की जा सकेगी और उसके तथा किसी ऐसे साक्षी के, जिसे वह अपने समर्थन में बुलाता है, साक्ष्य की, उस व्यक्ति की ओर से जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है तथा अभियोजक द्वारा, प्रतिपरीक्षा की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि नियोजक द्वारा वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति आरोप की सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है तो न्यायालय सुनवाई को, समय-समय पर, तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए, स्थगित कर देगा और यदि वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति उक्त कालावधि की समाप्ति तक भी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है तो न्यायालय नियोजक के विरुद्ध आरोप की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और, यदि अपराध साबित हो जाए तो, नियोजक को दोषसिद्ध करेगा।

अपराधों का
संज्ञान।

11. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिव्राद पर के सिवाय नहीं करेगा :

परन्तु जहां उपदान की रकम का संदाय या उसकी कसूली विहित समय के अवसान से छह मास के भीतर नहीं की गई है वहां समुचित सरकार नियंत्रक प्राधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत करेगी कि वह नियोजक के विरुद्ध परिव्राद करे और तब नियंत्रक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसा परिव्राद करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय नहीं करेगा।

12. इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नियंत्रक प्राधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

13. इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई उपदान किसी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय की किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

उपदान का संरक्षण।

14. इन अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्ध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत अथवा संविदा में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का अन्य अधिनियम-मितियों आदि पर अध्यारोही होना।

15. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 1976

क्र. 39593-इक्कीस-अ(वि. स.)-76.—भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 क, दिनांक 21 मई, 1975 में प्रकाशित किये गये दो कोल माइन्स लेबर वेल्फेयर फण्ड (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1972 (क्रमांक 70 सन् 1972) के हिन्दी अनुवाद को, जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (क्रमांक 19 सन् 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, अतः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सं. जु सुराणा, सचिव.

THE PAYMENT OF GRATUITY ACT, 1972

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

1. Short title, extent, application and commencement.
2. Definitions.
- 2A. Continuous service.
3. Controlling authority.
4. Payment of gratuity.
- 4A. Compulsory insurance.
5. Power to exempt.
6. Nomination.
7. Determination of the amount of gratuity.
- 7A. Inspectors.
- 7B. Powers of Inspectors.
8. Recovery of gratuity.
9. Penalties.
10. Exemption of employer from liability in certain cases.
11. Cognizance of offences.
12. Protection of action taken in good faith.
13. Protection of gratuity.
14. Act to override other enactments, etc.
15. Power to make rules.

THE PAYMENT OF GRATUITY ACT, 1972

ACT NO. 39 OF 1972

[21st August, 1972.]

An Act to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oilfields, plantations, ports, railway companies, shops or other establishments and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent, application and commencement.—(1) This Act may be called the Payment of Gratuity Act, 1972.

(2) It extends to the whole of India:

Provided that in so far as it relates to plantations or ports, it shall not extend to the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall apply to—

(a) every factory, mine, oilfield, plantation, port and railway company;

(b) every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a State, in which ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months;

(c) such other establishments or class of establishments, in which ten or more employees are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months, as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.

¹[(3A) A shop or establishment to which this Act has become applicable shall continue to be governed by this Act notwithstanding that the number of persons employed therein at any time after it has become so applicable falls below ten.]

(4) It shall come into force on such date² as the Central Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “appropriate Government” means,—

(i) in relation to an establishment—

(a) belonging to, or under the control of, the Central Government,

(b) having branches in more than one State,

(c) of a factory belonging to, or under the control of, the Central Government,

(d) of a major port, mine, oilfield or railway company, the Central Government,

(ii) in any other case, the State Government;

(b) “completed year of service” means continuous service for one year;

³[(c) “continuous service” means continuous service as defined in section 2A;]

(d) “controlling authority” means an authority appointed by the appropriate Government under section 3;

1. Ins. by Act 26 of 1984, s. 2 (w.e.f. 18-5-1984).

2. 16th September, 1972, *vide* notification No. S.O. 601(E), dated 16th September, 1972, *see* Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3(ii).

3. Subs. by Act 26 of 1984, s. 3, for clause (c) and the *Explanations* (w.e.f. 18-5-1984).

¹[(e) “employee” means any person (other than an apprentice) who is employed for wages, whether the terms of such employment are express or implied, in any kind of work, manual or otherwise, in or in connection with the work of a factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company, shop or other establishment to which this Act applies, but does not include any such person who holds a post under the Central Government or a State Government and is governed by any other Act or by any rules providing for payment of gratuity;]

(f) “employer” means, in relation to any establishment, factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company or shop—

(i) belonging to, or under the control of, the Central Government or a State Government, a person or authority appointed by the appropriate Government for the supervision and control of employees, or where no person or authority has been so appointed, the head of the Ministry or the Department concerned,

(ii) belonging to, or under the control of, any local authority, the person appointed by such authority for the supervision and control of employees or where no person has been so appointed, the chief executive officer of the local authority,

(iii) in any other case, the person, who, or the authority which, has the ultimate control over the affairs of the establishment, factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company or shop, and where the said affairs are entrusted to any other person, whether called a manager, managing director or by any other name, such person;

(g) “factory” has the meaning assigned to it in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);

(h) “family”, in relation to an employee, shall be deemed to consist of—

(i) in the case of a male employee, himself, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents ²[and the dependent parents of his wife and the widow] and children of his predeceased son, if any,

(ii) in the case of a female employee, herself, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and the dependent parents of her husband and the widow and children of her predeceased son, if any:

³* * * * *

Explanation.—Where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family, and where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is, under the personal law of the person making such adoption, lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee;

(i) “major port” has the meaning assigned to it in clause (8) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);

(j) “mine” has the meaning assigned to it in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

⁴[(k) “notification” means a notification published in the Official Gazette and the expression “notified” shall be construed accordingly];

(l) “oilfield” has the meaning assigned to it in clause (e) of section 3 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948);

1. Subs. by Act 47 of 2009, s. 2, for clause (e) (w.e.f. 3-4-1997).

2. Subs. by Act 22 of 1987, s. 2, for “and the widow” (w.e.f. 1-10-1987).

3. The proviso omitted by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 1-10-1987).

4. Subs. by Act 12 of 2018, s. 2, for clause (k) (w.e.f. 29-3-2018).

(m) “plantation” has the meaning assigned to it in clause (f) of section 2 of the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951);

(n) “port” has the meaning assigned to it in clause (4) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);

(o) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(p) “railway company” has the meaning assigned to it in clause (5) of section 3 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890);

(q) “retirement” means termination of the service of an employee otherwise than on superannuation;

¹[(r) “superannuation”, in relation to an employee, means the attainment by the employee of such age as is fixed in the contract or conditions of service as the age on the attainment of which the employee shall vacate the employment;]

(s) “wages” means all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or are payable to him in cash and includes dearness allowance but does not include any bonus, commission, house rent allowance, overtime wages and any other allowance.

²[**2A. Continuous service.**—For the purposes of this Act,—

(1) an employee shall be said to be in continuous service for a period if he has, for that period, been in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness, accident, leave, absence from duty without leave (not being absence in respect of which an order ³*** treating the absence as break in service has been passed in accordance with the standing orders, rules or regulations governing the employees of the establishment), lay-off, strike or a lock-out or cessation of work not due to any fault of the employee, whether such uninterrupted or interrupted service was rendered before or after the commencement of this Act;

(2) where an employee (not being an employee employed in a seasonal establishment) is not in continuous service within the meaning of clause (1), for any period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under the employer—

(a) for the said period of one year, if the employee during the period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—

(i) one hundred and ninety days, in the case of an employee employed below the ground in a mine or in an establishment which works for less than six days in a week; and

(ii) two hundred and forty days, in any other case;

(b) for the said period of six months, if the employee during the period of six calendar months preceding the date with reference to which the calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—

(i) ninety-five days, in the case of an employee employed below the ground in a mine or in an establishment which works for less than six days in a week; and

(ii) one hundred and twenty days, in any other case.

1. Subs. by Act 25 of 1984, s. 2, for clause (r) (w.e.f. 1-7-1984).

2. Ins. by Act 26 of 1984, s. 4 (w.e.f. 18-5-1984).

3. The words “imposing a punishment or penalty or” omitted by Act 22 of 1987, s. 3 (w.e.f. 1-10-1987).

¹[*Explanation.*—For the purposes of clause (2), the number of days on which an employee has actually worked under an employer shall include the days on which—

(i) he has been laid-off under an agreement or as permitted by standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), or under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), or under any other law applicable to the establishment;

(ii) he has been on leave with full wages, earned in the previous year;

(iii) he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment; and

(iv) in the case of a female, she has been on maternity leave; so, however, that the total period of such maternity leave does not exceed ²[such period as may be notified by the Central Government from time to time];]

(3) where an employee, employed in a seasonal establishment, is not in continuous service within the meaning of clause (1), for any period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under the employer for such period if he has actually worked for not less than seventy-five per cent. of the number of days on which the establishment was in operation during such period.]

3. Controlling authority.—The appropriate Government may, by notification, appoint any officer to be a controlling authority, who shall be responsible for the administration of this Act and different controlling authorities may be appointed for different areas.

4. Payment of gratuity.—(1) Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years,—

(a) on his superannuation, or

(b) on his retirement or resignation, or

(c) on his death or disablement due to accident or disease:

Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement:

³[Provided further that in the case of death of the employee, gratuity payable to him shall be paid to his nominee or, if no nomination has been made, to his heirs, and where any such nominees or heirs is a minor, the share of such minor, shall be deposited with the controlling authority who shall invest the same for the benefit of such minor in such bank or other financial institution, as may be prescribed, until such minor attains majority.]

Explanation.—For the purposes of this section, disablement means such disablement as incapacitates an employee for the work which he was capable of performing before the accident or disease resulting in such disablement.

(2) For every completed year of service or part thereof in excess of six months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of fifteen days' wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned:

Provided that in the case of a piece-rated employee, daily wages shall be computed on the average of the total wages received by him for a period of three months immediately preceding the termination of his employment, and, for this purpose, the wages paid for any overtime work shall not be taken into account:

1. *Explanation* inserted by Act 22 of 1987, s. 3 (w.e.f. 1-10-1987).

2. Subs. by Act 12 of 2018, s. 3, for "twelve weeks" (w.e.f. 29-3-2018).

3. Subs. by Act 22 of 1987, s. 4, for the second proviso (w.e.f. 1-10-1987).

Provided further that in the case of ¹[an employee who is employed in a seasonal establishment and who is not so employed throughout the year], the employer shall pay the gratuity at the rate of seven days' wages for each season.

²[*Explanation.*—In the case of a monthly rated employee, the fifteen days' wages shall be calculated by dividing the monthly rate of wages last drawn by him by twenty-six and multiplying the quotient by fifteen.]

(3) The amount of gratuity payable to an employee shall not exceed ³[⁴[such amount as may be notified by the Central Government from time to time]].

(4) For the purpose of computing the gratuity payable to an employee who is employed, after his disablement, on reduced wages, his wages for the period preceding his disablement shall be taken to be the wages received by him during that period, and his wages for the period subsequent to his disablement shall be taken to be the wages as so reduced.

(5) Nothing in this section shall affect the right of an employee receive better terms of gratuity under any award or agreement or contract with the employer.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) the gratuity of an employee, whose services have been terminated for any act, wilful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of, property belonging to the employer, shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused;

(b) the gratuity payable to an employee ⁵[may be wholly or partially forfeited]—

(i) if the services of such employee have been terminated for his riotous or disorderly conduct or any other act violence on his part, or

(ii) if the services of such employee have been terminated for any act which constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of his employment.

⁶*

*

*

*

*

⁷[**4A. Compulsory insurance.**—(1) With effect from such date as may be notified by the appropriate Government in this behalf, every employer, other than an employer or an establishment belonging to, or under the control of, the Central Government or a State Government, shall, subject to the provisions of sub-section (2), obtain an insurance in the manner prescribed, for his liability for payment towards the gratuity under this Act, from the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956) or any other prescribed insurer:

Provided that different dates may be appointed for different establishments or class of establishments or for different areas.

(2) The appropriate Government may, subject to such conditions as may be prescribed, exempt every employer who had already established an approved gratuity fund in respect of his employees and who desires to continue such arrangement, and every employer employing five hundred or more persons who establishes an approved gratuity fund in the manner prescribed from the provisions of sub-section (1).

(3) For the purpose of effectively implementing the provisions of this section, every employer shall within such time as may be prescribed get his establishment registered with the controlling authority in the prescribed manner and no employer shall be registered under the provisions of this section unless he

1. Subs. by Act 25 of 1984, s. 3, for “an employee employed in a seasonal establishment” (w.e.f. 1-7-1984).

2. *Explanation* inserted by Act 22 of 1987, s. 4 (w.e.f. 1-10-1987).

3. Subs. by Act 15 of 2010, s. 2, for “three lakhs and fifty thousand rupees” (w.e.f. 24-5-2010).

4. Subs. by Act 12 of 2018, s. 4, for “ten lakh rupees” (w.e.f. 29-3-2018).

5. Subs. by Act 25 of 1984, s. 3, for “shall be wholly forfeited” (w.e.f. 1-7-1984).

6. Sub-section (7) omitted by Act 34 of 1994, s. 3 (w.e.f. 24-5-1994).

7. Ins. by Act 22 of 1987, s. 5 (w.e.f. 1-10-1987).

has taken an insurance referred to in sub-section (1) or has established an approved gratuity fund referred to in sub-section (2).

(4) The appropriate Government may, by notification, make rules to give effect to the provisions of this section and such rules may provide for the composition of the Board of Trustees of the approved gratuity fund and for the recovery by the controlling authority of the amount of the gratuity payable to an employee from the Life Insurance Corporation of India or any other insurer with whom an insurance has been taken under sub-section (1), or as the case may be, the Board of Trustees of the approved gratuity fund.

(5) Where an employer fails to make any payment by way of premium to the insurance referred to in sub-section (1) or by way of contribution to an approved gratuity fund referred to in sub-section (2), he shall be liable to pay the amount of gratuity due under this Act (including interest, if any, for delayed payments) forthwith to the controlling authority.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (5) shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one thousand rupees for each day during which the offence continues.

Explanation.—In this section “approved gratuity fund” shall have the same meaning as in clause (5) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).]

5. Power to exempt.—¹[(1)] The appropriate Government may, by notification, and subject to such conditions as may be specified in the notification, exempt any establishment, factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company or shop to which this Act applies from the operation of the provisions of this Act if, in the opinion of the appropriate Government, the employees in such establishment, factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company or shop are in receipt of gratuity or pensionary benefits not less favourable than the benefits conferred under this Act.

²[(2) The appropriate Government may, by notification and subject to such conditions as may be specified in the notification, exempt any employee or class of employees employed in any establishment, factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company or shop to which this Act applies from the operation of the provisions of this Act, if, in the opinion of the appropriate Government, such employee or class of employees are in receipt of gratuity or pensionary benefits not less favourable than the benefits conferred under this Act.]

³[(3) A notification issued under sub-section (1) or sub-section (2) may be issued retrospectively a date not earlier than the date of commencement of this Act, but no such notification shall be issued so as to prejudicially affect the interests of any person.]

6. Nomination.—(1) Each employee, who has completed one year of service, shall make, within such time, in such form and in such manner, as may be prescribed, nomination for the purpose of the second proviso to sub-section (1) of section 4.

(2) An employee may, in his nomination, distribute the amount of gratuity payable to him under this Act amongst more than one nominee.

(3) If an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be made in favour of one or more members of his family, and any nomination made by such employee in favour of a person who is not a member of his family shall be void.

(4) If at the time of making a nomination the employee has no family, the nomination may be made in favour of any person or persons but if the employee subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith become invalid and the employee shall make, within such time as may be prescribed, a fresh nomination in favour of one or more members of his family.

1. Section 5 renumbered as sub-section (1) thereof by Act 26 of 1984, s. 5 (w.e.f. 18-5-1984).

2. Ins. by s. 5, *ibid.* (w.e.f. 18-5-1984).

3. Ins. by Act 22 of 1987, s. 6 (w.e.f. 1-10-1987).

(5) A nomination may, subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), be modified by an employee at any time, after giving to his employer a written notice in such form and in such manner as may be prescribed, of his intention to do so.

(6) If a nominee predeceases the employee, the interest of the nominee shall revert to the employee who shall make a fresh nomination, in the prescribed form, in respect of such interest.

(7) Every nomination, fresh nomination or alteration of nomination, as the case may be, shall be sent by the employee to his employer, who shall keep the same in his safe custody.

7. Determination of the amount of gratuity.—(1) A person who is eligible for payment of gratuity under this Act or any person authorised, in writing, to act on his behalf shall send a written application to the employer, within such time and in such form, as may be prescribed, for payment of such gratuity.

(2) As soon as gratuity becomes payable, the employer shall, whether an application referred to in sub-section (1) has been made or not, determine the amount of gratuity and give notice in writing to the person to whom the gratuity is payable and also to the controlling authority specifying the amount of gratuity so determined.

¹[(3) The employer shall arrange to pay the amount of gratuity within thirty days from the date it becomes payable to the person to whom the gratuity is payable.

(3A) If the amount of gratuity payable under sub-section (3) is not paid by the employer within the period specified in sub-section (3), the employer shall pay, from the date on which the gratuity becomes payable to the date on which it is paid, simple interest at such rate, not exceeding the rate notified by the Central Government from time to time for repayment of long-term deposits, as that Government may, by notification specify:

Provided that no such interest shall be payable if the delay in the payment is due to the fault of the employee and the employer has obtained permission in writing from the controlling authority for the delayed payment on this ground.]

(4)(a) If there is any dispute as to the amount of gratuity payable to an employee under this Act or as to the admissibility of any claim of, or in relation to, an employee for payment of gratuity, or as to the person entitled to receive the gratuity, the employer shall deposit with the controlling authority such amount as he admits to be payable by him as gratuity.

²* * * *

³[(b) Where there is a dispute with regard to any matter or matters specified in clause (a), the employer or employee or any other person raising the dispute may make an application to the controlling authority for deciding the dispute.]

⁴[(c) The controlling authority shall, after due inquiry and after giving the parties to the dispute a reasonable opportunity of being heard, determine the matter or matters in dispute and if, as a result of such inquiry any amount is found to be payable to the employee, the controlling authority shall direct the employer to pay such amount or, as the case may be, such amount as reduced by the amount already deposited by the employer.]

⁵[(d)] The controlling authority shall pay the amount deposited, including the excess amount, if any, deposited by the employer, to the person entitled thereto.

⁶[(e)] As soon as may be after a deposit is made under clause (a), the controlling authority shall pay the amount of the deposit—

(i) to the applicant where he is the employee; or

1. Subs. by Act 22 of 1987, s. 7, for sub-section (3) (w.e.f. 1-10-1987).

2. The *Explanation* omitted by Act 25 of 1984, s. 4 (w.e.f. 1-7-1984).

3. Ins. by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 1-7-1984).

4. Subs. by s. 4, *ibid.*, for clause (c) (w.e.f. 1-7-1984).

5. Clause (c) re-lettered as clause (d) thereof by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 1-7-1984).

6. Clause (d) re-lettered as clause (e) thereof by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 1-7-1984).

(ii) where the applicant is not the employee, to the ¹[nominee or, as the case may be, the guardian of such nominee or] heir of the employee if the controlling authority is satisfied that there is no dispute as to the right of the applicant to receive the amount of gratuity.

(5) For the purpose of conducting an inquiry under sub-section (4), the controlling authority shall have the same powers as are vested in a court, while trying a suit, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

(a) enforcing the attendance of any person or examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) issuing commissions for the examination of witnesses.

(6) Any inquiry under this section shall be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196, of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(7) Any person aggrieved by an order under sub-section (4) may, within sixty days from the date of the receipt of the order, prefer an appeal to the appropriate Government or such other authority as may be specified by the appropriate Government in this behalf:

Provided that the appropriate Government or the appellate authority, as the case may be, may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the said period of sixty days, extend the said period by a further period of sixty days:

²[Provided further that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant either produces a certificate of the controlling authority to the effect that the appellant has deposited with him an amount equal to the amount of gratuity required to be deposited under sub-section (4), or deposits with the appellate authority such amount.]

(8) The appropriate Government or the appellate authority, as the case may be, may, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard, confirm, modify or reverse the decision of the controlling authority.

³[**7A. Inspectors.**—(1) The appropriate Government may, by notification, appoint as many Inspectors, as it deems fit, for the purposes of this Act.

(2) The appropriate Government may, by general or special order, define the area to which the authority of an Inspector so appointed shall extend and where two or more Inspectors are appointed for the same area, also provide by such order, for the distribution or allocation of work to be performed by them under this Act.

(3) Every Inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

7B. Powers of Inspectors.—(1) Subject to any rules made by the appropriate Government in this behalf, an Inspector may, for the purpose of ascertaining whether any of the provisions of this Act or the conditions, if any, of any exemption granted thereunder, have been complied with, exercise all or any of the following powers, namely:—

(a) require an employer to furnish such information as he may consider necessary;

(b) enter and inspect, at all reasonable hours, with such assistants (if any), being persons in the service of the Government or local or any public authority, as he thinks fit, any premises of or place in any factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company, shop or other establishment to which this Act, applies, for the purpose of examining any register, record or notice or other document required to be kept or exhibited under this Act or the rules made thereunder, or otherwise kept or

1. Subs. by Act 25 of 1984, s. 4, for “nominee” (w.e.f. 1-7-1984).

2. The proviso ins. by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 1-7-1984).

3. Ins. by s. 5, *ibid.* (w.e.f. 1-7-1984).

exhibited in relation to the employment of any person or the payment of gratuity to the employees, and require the production thereof for inspection;

(c) examine with respect to any matter relevant to any of the purposes aforesaid, the employer or any person whom he finds in such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is an employee employed therein;

(d) make copies of, or take extracts from, any register, record, notice or other document, as he may consider relevant, and where he has reason to believe that any offence under this Act has been committed by an employer, search and seize with such assistance as he may think fit, such register, record, notice or other document as he may consider relevant in respect of that offence;

(e) exercise such other powers as may be prescribed.

(2) Any person required to produce any register, record, notice or other document or to give any information by an Inspector under sub-section (1) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of sections 175 and 176 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of that Code.]

8. Recovery of gratuity.—If the amount of gratuity payable under this Act is not paid by the employer, within the prescribed time, to the person entitled thereto, the controlling authority shall, on an application made to it in this behalf by the aggrieved person, issue a certificate for that amount to the Collector, who shall recover the same, together with compound interest thereon ¹[at such rate as the Central Government may, by notification, specify], from the date of expiry of the prescribed time, as arrears of land revenue and pay the same to the person entitled thereto:

²[Provided that the controlling authority shall, before issuing a certificate under this section, give the employer a reasonable opportunity of showing cause against the issue of such certificate:

Provided further that the amount of interest payable under this section shall, in no case exceed the amount of gratuity payable under this Act.]

9. Penalties.—(1) Whoever, for the purpose of avoiding any payment to be made by himself under this Act or of enabling any other person to avoid such payment, knowingly makes or causes to be made any false statement or false representation shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ³[ten thousand rupees], or with both.

(2) An employer who contravenes, or makes default in complying with, any of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term ⁴[which shall not be less than three months but which may extend to one year, or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees, or with both]:

Provided that where the offence relates to non-payment of any gratuity payable under this Act, the employer shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ⁵[six months but which may extend to two years] unless the court trying the offence, for reasons to be recorded by it in writing, is of opinion that a lesser term of imprisonment or the imposition of a fine would meet the ends of justice.

10. Exemption of employer from liability in certain cases.—Where an employer is charged with an offence punishable under this Act, he shall be entitled, upon complaint duly made by him and on giving to the complainant not less than three clear days' notice in writing of his intention to do so, to have any other person whom he charges as the actual offender brought before the court at the time appointed for

1. Subs. by Act 22 of 1987, s. 8, for "at the rate of nine per cent. per annum" (w.e.f. 1-10-1987).

2. The provisos inserted by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 1-10-1987).

3. Subs. by s. 9, *ibid.*, for "one thousand rupees" (w.e.f. 1-10-1987).

4. Subs. by s. 9, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 1-10-1987).

5. Subs. by s. 9, *ibid.*, for "three months" (w.e.f. 1-10-1987).

hearing the charge; and if, after the commission of the offence has been proved, the employer proves to the satisfaction of the court—

(a) that he has used due diligence to enforce the execution of this Act, and

(b) that the said other person committed the offence in question without his knowledge, consent or connivance,

that other person shall be convicted of the offence and shall be liable to the like punishment as if he were the employer and the employer shall be discharged from any liability under this Act in respect of such offence:

Provided that in seeking to prove as aforesaid, the employer may be examined on oath and his evidence and that of any witness whom he calls in his support shall be subject to cross-examination on behalf of the person he charges as the actual offender and by the prosecutor:

Provided further that, if the person charged as the actual offender by the employer cannot be brought before the court at the time appointed for hearing the charge, the court shall adjourn the hearing from time to time for a period not exceeding three months and if by the end of the said period the person charged as the actual offender cannot still be brought before the court, the court shall proceed to hear the charge against the employer and shall, if the offence be proved, convict the employer.

11. Cognizance of offences.—(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act save on a complaint made by or under the authority of the appropriate Government:

Provided that where the amount of gratuity has not been paid, or recovered, within six months from the expiry of the prescribed time, the appropriate Government shall authorise the controlling authority to make a complaint against the employer, whereupon the controlling authority shall, within fifteen days from the date of such authorisation, make such complaint to a magistrate having jurisdiction to try the offence.

(2) No court inferior to that of a ¹[Metropolitan magistrate or a Judicial Magistrate of the first class] shall try any offence punishable under this Act.

12. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceeding shall lie against the controlling authority or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

13. Protection of gratuity.—No gratuity payable under this Act ²[and no gratuity payable to an employee employed in any establishment, factory, mine, oilfield, plantation, port, railway company or shop exempted under section 5] shall be liable to attachment in execution of any decree or order of any civil, revenue or criminal court.

14. Act to override other enactments, etc.—The provisions of this Act or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or in any instrument or contract having effect by virtue of any enactment other than this Act.

15. Power to make rules.—(1) The appropriate Government may, by notification, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

1. Subs. by Act 34 of 1994, s. 4, for “Presidency Magistrate or a Magistrate of the first class” (w.e.f. 24-5-1994).

2. Ins. by Act 25 of 1984, s. 6 (w.e.f. 1-7-1984).